राज्य बिजली बोर्ड पर कोयला राशि की वसूली

939. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों पर कोल इंडिया लिमिटेड की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) इस राशि की वसूली के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) विभिन्न राज्यों को कोयले की पूर्ति किस दर पर की जाती है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कोयला कम्पनियों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार दिनांक 30-9-91 की स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड तथा अन्य विद्युत उपयोगिताओं की ओर देय कुल बकाया राशि 1923.35 करोड़ रु० थी ।

(ख) उपर्युक्त देय बकाया राशि की वसूली किये जाने के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. दिनांक 1-10-92 से कोयला मंत्रालय ने चालू कोयला आपूर्ति को अग्रिम अदायगी के साथ सयोजित किये जाने की पद्धति पहले ही शरू कर दी है ।

2. दिनांक 1-4-1989 के बाद चालू की गई सभी विद्युत यूनिटों को, पूर्व में भी केवल अग्रिम अदायगी के एवज में रिवोलविंग सेंटर आफ क्रैडिट के एवज में ही कोयले की आपूर्ति की जा रही थी ।

3. राज्य सरकारों से राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा शीघ्र ही बकाया देय राशि का निपटारा किये जा के संबंध में कार्रवाई करने अथवा उनकी सहायता करने के संबंध में अनुरोध किया गया है ।

4. भारत सरकार ने 31-5-1990 की स्थिति के अनुसार सभी अविवादित कोयले की बिक्री की राशि को, सभी राज्य सरकारों को देय राज्य योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता की राशि के एवज में जिन राज्यों के विद्युत बोर्ड तथा विद्युत उपयोगिताएं दोषी पाई गई हैं, उनसे 4 वर्ष की अवधि में चार बराबर की किस्तों में, अदायगी का समायोजन किये जाने के निर्णय का समायोजन किये जाने का निर्णय लिया है । कोल इंडिया लिमिटेड के मामले में प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि लगभग 273 करोड़ रुपये की होगी ।

इन उपायों को क्रियान्वित किये जाने से राज्य विद्युत बोर्डों तथा विद्युत उपयोगिताओं की ओर बकाया कुल राशि काफी सीमा तक कम आ जाने की संभावना है ।

(ग) कोयले की जिस कीमत पर उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है, उसमें कोयले के ग्रेड के अनुसार अन्तराल है । कोल इंडिया लि० द्वारा उत्पादित कोयले की वर्तमान में निर्धारित पिट-हैड कीमत औसतन 249 रु. प्रति टन और सिंगरेनी कोलिवरीज कम्पनी लि० के मामले में 297 रु० प्रति टन है ।

Losses incurred by BCCL

940. **SHRI RAM NARESH YADAV:** Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government's attention have been drawn to the news-item captioned "Koyala Bechane ki Galatnitise B.C.C.L. Ko Karoron Ka Ghata" Loss of crores of rupees to the B.C.C.L. due to faulty policy regarding sales of coal published in 'Jan-Satta' of the November, 1991; and